

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 176
उत्तर देने की तारीख-14.09.2020

ऑनलाइन शिक्षा का मानकीकरण

176. श्री पी० पी० चौधरी:
श्री सुनील कुमार सिंह:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कई शैक्षिक प्रतिष्ठानों में कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षा के मानकीकरण पर कोई सिफारिश जारी की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या वर्ग विशेष की प्रकृति में परिवर्तन के कारण देश भर में एक समान तरीके से मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रथाओं को बदलने के लिए उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार की माध्यमिक शिक्षा के लिए दीर्घकालिक डिजिटल शिक्षा रणनीति बनाने की योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख) : ऑनलाइन शिक्षा के मानकीकरण किए जाने के संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) को प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के डिग्री कार्यक्रम ऑनलाइन प्रदान करने के लिए पहले यूजीसी (ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) विनियम, 2018 अधिसूचित किया था। तथापि, हाल ही में यूजीसी ने एचईआई द्वारा ओडीएल और ऑनलाइन में गुणवत्ता बनाए रखने हेतु पूर्व 2018 के विनियम का अधिक्रमण करते हुए मानकों का एक नया सेट-यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम एवं ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 को भारत के अधिकारिक राजपत्र में 04 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया है। इन नए विनियमों को यूजीसी की वेबसाइट <https://www.ugc.ac.in/pdfnews/221580.pdf> पर अपलोड किया गया है।

(ग) : कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने देश के विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर संबंधी दिशा निर्देश 29.04.2020 को जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुक्रम में आयोग ने 06.07.2020 को संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं जिसमें वैकल्पिक आकलन उपायों आदि हेतु संभावना शामिल हैं। ये दिशानिर्देश यूजीसी की वेबसाइट <https://www.ugc.ac.in/pdfnews/6100894> UGC-Revised-Guidelines-on-Examinations-and-Academic-Calendar-for-the-Universities-in-view-of-COVID-19-Pandemic 06 07 2020.pdf पर उपलब्ध हैं।

(घ) : माध्यमिक शिक्षा के लिए डिजिटल शिक्षा कार्यनीति के संबंध में, पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है जो डिजिटल / ऑनलाइन / ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है ताकि शिक्षा के लिए बहु-मोड का उपयोग किया जा सके। इससे देशभर के लगभग 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को फायदा होगा। पहल में शामिल हैं:

- राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल ढांचा: और सभी ग्रेड (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोडित एनर्जेटिक पाठ्यपुस्तकें
- कक्षा 1 से 12 तक प्रति वर्ग टीवी चैनल (एक वर्ग, एक चैनल)
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट- शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग
- डिजिटल रूप से सुगम्य सूचना प्रणाली (डेजी) पर विकसित और दृष्टिबाधितों के लिए विशेष ई-सामग्री और एनआईओएस वेबसाइट / यू-ट्यूब पर सांकेतिक भाषा में।
